अरविंद कुमार

बनाम

यू. पी. राज्य और अन्य

(सिविल अपील संख्या 7165/2016)

अगस्त 08,2016

[दीपक मिश्रा और आर. एफ. नरीमन, न्यायाधिपति]

यू. पी. भूमि धारण (संशोधन) अधिनियम, 1976 पर अधिकतम सीमा अधिरोपण -की धारा 31(2) - अधिकतम सीमा की कार्यवाही में कमी -1960 अधिनियम (प्रधान अधिनियम) धारा 10(2) के तहत नोटिस विचाराधीन भूमि को अधिशेष भूमि के रूप में घोषित करने के प्रस्ताव के लिए किरायेदार-धारक को दिया - अपीलकर्ताओं (खातेदार के कानूनी उत्तराधिकारी) द्वारा दायर आपत्तियां- इस बीच, अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकरण के द्वारा आदेश दिनांक 13.1.1975 को पारित हुआ समस्त भूमि जो कि नोटिस की विषयवस्तु थी, को अधिशेष घोषित कर दिया - इस आदेश के विरुद्ध अपील दिनांक 13.12.87 को खारिज़ कर दी गई, अपीलकर्ताओं की रिट याचिका भी खारिज़ कर दी गई - अपीलकर्ताओं की दलील कि धारा 31 के सही निर्माण पर, 1976 संशोधन अधिनियम के तहत संपूर्ण कार्यवाही समाप्त हो गई थी और इसलिए, अपीलीय प्राधिकारी के पास दिनांक 13.12.87 को आदेश पारित करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था - ठहराया गया: धारा 31(2) के आवेदन के लिए दो पूर्व-आवश्यकताएं हैं जो आदेश के खिलाफ़ अपील को समाप्त करने का प्रावधान करती हैं अधिशेष भूमि का निर्धारण के आदेश के खिलाफ़ - प्रथम, 17.1.1975 से पूर्व के मूल अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का आदेश होना चाहिए, द्वितीय, ऐसी अधिशेष भूमि के संबंध में निर्धारित प्राधिकारी को अधिशेष भूमि का पुनः निर्धारण करना आवश्यक था धारा 9,1974 संशोधन अधिनियम

के तहत- स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला आदेश 17.1.1975 से चार दिन पहले किया गया था, इस प्रकार पहली पूर्व-अपेक्षा पूरी की गई - दूसरी पूर्व-अपेक्षा भी पूरी की गई क्योंकि निर्धारित प्राधिकारी की आवश्यकता थी धारा 9, 1974 संशोधन अधिनियम के अंतर्गत अधिशेष भूमि का पुनः निर्धारण करना लेकिन ऐसा कभी नहीं किया गया क्योंकि अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने का कोई आदेश नहीं था- धारा 31(2) की भाषा यह भी स्पष्ट करती है कि ऐसे आदेशों के खिलाफ़ की गई और 10.10.1975 से पहले लंबित प्रत्येक अपील को माना जाएगा उक्त देय तिथि पर समाप्त हो गई है और इस प्रकार वर्तमान मामले में अपील 10.10.1975 से पहले दायर की गई थी, उक्त तिथि पर समाप्त हो गई - यू.पी. भूमि धारण अधिनियम, 1960 सीमा का अधिरोपण- यू.पी.भूमि धारण सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972- धारा 19- यू.पी. भूमि धारण सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 धारा 9 ।

यू.पी.भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974-धारा 9 अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता - निर्धारित प्राधिकारी में कोई विवेकाधिकार निहित नहीं है - माना गया: ऐसी आवश्यकता विवेकाधीन नहीं है क्योंकि अभिव्यक्ति "दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय हो सकती है" वर्ष..." धारा 9 में हो रहा है, 1974 संशोधन अधिनियम धारा 31(3), 1976 संशोधन अधिनियम में भी होता है और इस प्रकार उप-धारा के सही पढ़ने पर, निर्धारित प्राधिकारी को, हर मामले में, अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता होती है यदि अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाले आदेश को 10.10.1975 से पहले बनाया गया था।

कोर्ट ने अपील स्वीकार करते हुए अभिनिर्धारित किया:

1.1 यू.पी. की मूल वैधानिक योजना। भूमि धारण अधिनियम, 1960 (प्रधान अधिनियम) पर सीमा का अधिरोपण, जिसमें अधिशेष "उचित गुणवत्ता वाली भूमि" की बात की गई थी, को 1974 के संशोधन अधिनियम के साथ पढ़े गए 1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा एक पूरी तरह से नई और अलग योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। ये दोनों अधिनियम, कुछ मामूली अपवादों के साथ, एक ही तारीख, अर्थात् 8.6.1973 को लागू हुए। 1974 संशोधन अधिनियम की धारा 9 को लागू करने के लिए, संशोधन अधिनियम के शुरू होने से पहले एक खातेदार के संबंध में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का आदेश दिया जाना चाहिए। धारा 1(2) द्वारा, "यह धारा" और धारा 9 दोनों एक साथ यानि 17.1.1975 को लागू हुईं। अभिव्यक्ति "यह धारा" धारा 1(1) को संदर्भित करती है जो बदले में अधिनियम को यू.पी. भूमि धारण पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 के रूप में संदर्भित करती है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम केवल 17.1.1975,को शुरू हुआ था , हालांकि कई धाराएं पूर्वव्यापी यानी 8.6.1973 को लागू मानी जाएंगी। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश 13.1.1975 को होने के कारण, धारा 9 की पहली शर्त पूरी होती है, अर्थात यह आदेश 17.1.1975 से पहले पारित किया गया था। [अनुच्छेद 12][732-एफ, जी-II; 733-ए-सी]

1.2 यह अभिव्यक्ति "दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय हो सकती है..." धारा 9, में आती है यू.पी. में भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 संशोधन अधिनियम 1976 की धारा 31(3) में भी होता है। यह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि अभिव्यक्ति "हो सकता है" शब्दों के साथ चलती है “दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय पर..." जैसा कि स्पष्ट है कि उप-धारा का सही वाचन, निर्धारित प्राधिकारी था, प्रत्येक मामले में, अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने के लिए यदि अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला आदेश अक्टूबर, 1975 के 10वें दिन से पहले किया गया था । विचार यह है कि अधिशेष भूमि को

फिर से निर्धारित करने के लिए दो साल की अवधि दी जाती है 1974 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार । इस मामले में, यह स्पष्ट है कि अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी में कोई विवेकाधिकार निहित नहीं है। सभी मामलों में, अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित किया जाना है, क्योंकि सभी भूमि पर लागू होने वाली एक पूरी तरह से अलग और नई योजना ने मौजूदा योजना का स्थान ले लिया है। [अनुच्छेद 12][733-सी-एफ]

2.1 धारा 31(2) के तहत, 1976 (संशोधन) अधिनियम, 1976 में निहित अस्थायी प्रावधान, स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला आदेश 17.1.1975 से चार दिन पहले किया गया था और इस प्रकार पहली शर्त या पूर्व -धारा 31 के आवेदन के लिए आवश्यक शर्तें पूरी हो गई हैं। दूसरी पूर्व-आवश्यकता भी इस साधारण कारण से पूरी की गई है कि 1974 अधिनियम की धारा 9, जो 1972 संशोधन अधिनियम के समान विधायी योजना का हिस्सा है, इस कारण से लागू होगी कि अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला आदेश पहले बनाया गया था उक्त अधिनियम के प्रारंभ के लिए, अर्थात्, 17.1.1975, (जो 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 31(2) के आवेदन के लिए पहली पूर्व-आवश्यकता के समान है)। ऐसा होने पर, धारा 31(2) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि ऐसे आदेशों के खिलाफ़ की गई प्रत्येक अपील और 10 अक्टूबर, 1975 से ठीक पहले लंबित, उक्त तिथि को समाप्त मानी जाएगी। तथ्यों पर, अपील इस तिथि से पहले दायर की गई थी। [अनुच्छेद 14][734-ए-डी]

2.2 इस प्रकार, 1976 अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार धारा 31(3) के तहत अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करना निर्धारित प्राधिकारी के लिए आवश्यक था। वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर ऐसा कभी नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि 1975 में दायर अपील समाप्त हो गई है और इसलिए अतिरिक्त आयुक्त, आगरा द्वारा योग्यता के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा होने

पर, आयुक्त द्वारा दिनांक 13.1.1975 को पारित निर्णय और आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है। [अनुच्छेद 15][734-डी, ई-एफ]

उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मिथिलेश कुमारी और अन्य 1987 (तितम्बा) एससीसी 21: मंसूर अली खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य (1992) 1 एससीसी 737: 1991 (2) तितम्बा एससीआर 159 - संदर्भित।

केस लॉज संदर्भ

1987 (तितम्बा) एससीसी 21	संदर्भित	अनुच्छेद 10
1991 (2) तितम्बा एससीआर 159	संदर्भित	अनुच्छेद 10

सिविल अपीलीय क्षेत्राधिकार: सिविल अपील संख्या 7165/2016

सिविल विविध में उच्च न्यायालय, इलाहाबाद के निर्णय एवं आदेश दिनांक 06.08.2007 से रिट याचिका संख्या 24142/1987।

चंद्र उदय सिंह, वरिष्ठ वकील, बिमल रॉय जड़, नरेश कुमार, वकील अपीलकर्ता के लिए.

एम. आर. शमशाद, टी. एन. सिंह, विकास, के. सिंह, उमंग त्रिपाठी, विनय गर्ग, तन्मय अग्रवाल, संदीप सिंह, सुश्री. दीपम गर्ग, वकील उत्तरदाताओं के लिए ।

न्यायालय का निर्णय इनके द्वारा सुनाया गया

आर.एफ. नरीमन, न्यायाधिपति. 1. वर्तमान मामले में न्यायालय को घने जंगल से गुजरना शामिल है जिसमें यू.पी. भूमि धारण सीमा का अधिरोपण अधिनियम, 1960 निहित है [इसके बाद इसे "मूल अधिनियम" के रूप में संदर्भित किया गया है] और

इसमें बनाए गए तीन संशोधन अधिनियम। दोनों पक्षों के विद्वान वकील की मदद से, हमने इन अधिनियमों की विभिन्न धाराओं और उप-धाराओं का अध्ययन किया है, केवल एक बुनियादी प्रश्न तय करने के उद्देश्य से: कि क्या प्रश्नगत भूमि के संबंध में सीलिंग की कार्यवाही 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 31 के कारण व्यपगत हो गई है।

2. वर्तमान मामले का निर्णय करने के लिए आवश्यक संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं । मूल अधिनियम की धारा 10(2) के तहत एक नोटिस दिया गया था भूमि-धारक, एक कमला देवी, आपत्तियां दर्ज करने के लिए 51.29 एकड़ भूमि को अधिशेष भूमि घोषित करने का प्रस्ताव के खिलाफ़। उक्त नोटिस के अनुसरण में , आपत्तियां स्वर्गीय कमला देवी और अपीलकर्ताओं 1 से 3 तक, उसके कानूनी उत्तराधिकारी द्वारा भी दायर की गईं थीं । अपीलकर्ताओं के अनुसार,अधिनियम के सही निर्माण के दौरान कोई अधिशेष भूमि नहीं थी। इस बीच, अधिनियम के तहत निर्धारित प्राधिकारी ने दिनांक 13.1.1975 को एक आदेश पारित किया जो उस संपूर्ण भूमि जो नोटिस की विषय वस्तु थी, को अधिशेष घोषित किया गया। निर्धारित प्राधिकारी के आदेश के विरुद्ध एक अपील दायर की गई आदेश का भी यही हश्र हुआ और 13.12.1987 को खारिज़ कर दिया गया। यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि एक तर्क उठाया गया था कि कार्यवाहियां समाप्त हो चुकी थीं, जिसके तर्क का उत्तर अपीलीय प्राधिकारी द्वारा दिया गया यह कहते हुए कि संशोधन अधिनियम की धारा 9(2) के तहत कोई नया नोटिस ज़ारी नहीं किया गया था और चूंकि ऐसा था, कार्यवाही समाप्त नहीं हुई थी। 1987 में दायर की गई एक रिट याचिका का अंततः 6.8.2007 को निपटारा कर दिया गया, जहाँ अपील के तहत निर्णय द्वारा रिट याचिका खारिज़ कर दी गई। कई बिंदुओं पर बहस हुई जिनसे फिलहाल हमारा कोई सरोकार नहीं है। उपशमन पर तर्क का वही हश्र हुआ जो अपीलीय प्राधिकारी के निर्णय का हुआ।

3. दोनों पक्षों के विद्वान वकील की दलीलों पर विचार करने से पहले, घोड़े को गाड़ी के आगे रखना सबसे महत्वपूर्ण है। अब मुख्य अधिनियम के साथ-साथ तीन संशोधन अधिनियमों का एक संक्षिप्त सर्वेक्षण किया जाना चाहिए।

4. 1960 का अधिनियम उत्तर प्रदेश राज्य में भूमि धारण पर सीमा लगाने का प्रावधान करने वाला एक अधिनियम है। मूल अधिनियम के तहत, एक खातेदार का अधिकतम क्षेत्र 40 एकड़ "उचित गुणवत्ता वाली भूमि" कहा गया था, और जहां खातेदार के परिवार में 5 से अधिक सदस्य हैं, ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र धारक को परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए 8 एकड़ उचित गुणवत्ता वाली भूमि जोड़नी होगी, जो अधिकतम 24 एकड़ होगी। मूल अधिनियम में "उचित गुणवत्ता वाली भूमि" को उस भूमि के रूप में परिभाषित किया गया था, जिसकी वंशानुगत दर अधिनियम के तहत 6/- रुपये प्रति एकड़ से अधिक है। सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले खातेदारों को एक सामान्य नोटिस दिया जाना था ताकि वे इसके संबंध में एक विवरण प्रस्तुत कर सकें। फिर अधिशेष भूमि का एक अर्ध-न्यायिक निर्धारण किया जाना है, जहां आपत्तियां दायर की जाती हैं और निर्धारित प्राधिकारी, पक्षों को सुनने और सबूत पेश करने का उचित अवसर देने के बाद, कारण दर्ज करने के बाद उनकी आपत्तियों पर निर्णय लेता है, और फिर अधिशेष भूमि की सीमा निर्धारित करें। जिला न्यायाधीश को एक अपील प्रदान की जाती है जिसका निर्णय तब अंतिम और निर्णायक माना जाता है। इसके बाद निर्धारित प्राधिकारी को निर्धारित अधिशेष भूमि को आधिकारिक राजपत्र में अधिसूचित करना होता है। ऐसी अधिसूचना की तारीख़ पर, ऐसी अधिशेष भूमि सभी बाधाओं से मुक्त होकर राज्य में निहित हो जाएगी, और उस तारीख़ को/उस तारीख़ से, सभी अधिकार, शीर्षक और ब्याज ऐसी भूमि के सभी व्यक्ति से नष्ट हो जायेंगे। मूल अधिनियम में अन्य बातों के साथ-साथ भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहकारी समितियों को अधिशेष भूमि के वितरण की मशीनरी शामिल है। भू-धारकों की अधिशेष भूमि को निहित करने के लिए मूल अधिनियम द्वारा मुआवजा दिया जाता है। इस प्रारंभिक नोट

के साथ, अब उपरोक्त अधिनियम की प्रासंगिक धाराओं को निर्धारित करना महत्वपूर्ण है ।

"धारा 3. परिभाषाएँ। इस अधिनियम में, जब तक कि संदर्भ के विषय में कुछ भी प्रतिकूल न हो -

(बी) "उचित गुणवत्ता वाली भूमि" का अर्थ वह भूमि है जिसकी वंशानुगत दर छह रुपये प्रति एकड़ से अधिक है;

धारा 4. सीमा क्षेत्र।

(1) इस अधिनियम के प्रावधानों के अधीन, किसी खातेदार पर लागू सीमा क्षेत्र की गणना राज्य में किसी भी होल्डिंग में उसके द्वारा अपने अधिकार में, चाहे वह अपने नाम पर हो या प्रकट रूप से किसी व्यक्ति के नाम पर ,सभी भूमि को ध्यान में रखकर की जाएगी।

(2) (ए) एक किरायेदार(खातेदार) का अधिकतम क्षेत्र चालीस एकड़ उचित गुणवत्ता वाली भूमि होगी।

(बी) जहां किरायेदार(खातेदार) के पास पांच से अधिक सदस्यों वाला परिवार है, या उसमें शामिल है, ऐसे खातेदार का अधिकतम क्षेत्र खंड (ए) में उल्लेखित क्षेत्र होगा, साथ ही परिवार के प्रत्येक अतिरिक्त सदस्य के लिए आठ एकड़ उचित गुणवत्ता वाली भूमि होगी अधिकतम ऐसी चौबीस एकड़ जमीन के अधीन:

बशर्ते कि, यदि किसी भी समय, परिवार में पांच से अधिक सदस्य नहीं होते हैं, तो खंड (ए) के तहत अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक खातेदार द्वारा रखी गई सभी भूमि, अधिशेष भूमि के रूप में मानी जाएगी।

स्पष्टीकरण - उचित गुणवत्ता वाली भूमि के अलावा अन्य भूमि के संबंध में इस उप-धारा के तहत सीमा क्षेत्र की गणना करते समय, डेढ़ एकड़ ऐसी भूमि,

जिसकी वंशानुगत दर चार रुपये प्रति एकड़ से अधिक है, लेकिन छह रुपये प्रति एकड़ से अधिक नहीं है एकड़, और दो एकड़ ऐसी भूमि, जिसकी वंशानुगत दर चार रुपये या प्रति एकड़ से कम है, एक एकड़ उचित गुणवत्ता वाली भूमि के बराबर मानी जाएगी।

धारा 5. मौजूदा भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण.-

(1) इस अधिनियम के लागू होने की तारीख़ से, कोई भी किरायेदार(खातेदार), इस अधिनियम द्वारा अन्यथा प्रदान किए गए को छोड़कर, उस पर लागू सीमा क्षेत्र से अधिक क्षेत्र रखने का हकदार नहीं होगा, किसी भी अन्य कानून में निहित कुछ भी,प्रथा, या उस समय लागू उपयोग, या समझौता, इसके विपरीत होते हुए भी।

(2) इस अधिनियम के प्रारंभ में एक खातेदार के लिए लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र का निर्धारण करने में, अगस्त, 1959 के बीसवें दिन के बाद किए गए भूमि के किसी भी हस्तांतरण या विभाजन, जो, हस्तांतरण या विभाजन के लिए, घोषित किया गया होता इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिशेष भूमि को नजरअंदाज कर दिया जाएगा और उस पर ध्यान नहीं दिया जाएगा।

(3) उपधारा (2) के प्रावधान इन पर लागू नहीं होंगे-

(ए) राज्य सरकार के पक्ष में स्थानांतरण;

(बी) विभाजन यू.पी. धारण समेकन अधिनियम, 1953, के तहत या

(सी) अगस्त, 1959 के बीसवें दिन लंबित एक मुकदमे या कार्यवाही द्वारा संयुक्त हिंदू परिवार की हिस्सेदारी का विभाजन।

धारा 9. अधिकतम सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले काश्तकारों को उनके संबंध में विवरण प्रस्तुत करने के लिए सामान्य सूचना - इस अधिनियम के

लागू होने की तारीख़ के बाद, जितनी जल्दी हो सके, निर्धारित प्राधिकारी, सामान्य सूचना द्वारा, प्रकाशित करेगा आधिकारिक राजपत्र में, इस अधिनियम के लागू होने की तिथि पर उस पर लागू सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले प्रत्येक खातेदार को नोटिस के प्रकाशन की तारीख़ से 30 दिनों के भीतर उसे प्रस्तुत करने के लिए कहें। उसकी सभी संपत्तियों का ऐसे प्रारूप में और ऐसे ब्यौरे देना जो निर्धारित किए जाएं। विवरण में उस भूखंड या भूखंडों का भी उल्लेख किया जाएगा जिसके लिए वह छूट का दावा करता है और उन भूखंडों का भी उल्लेख करेगा जिन्हें वह इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत उस पर लागू सीमा क्षेत्र के हिस्से के रूप में बनाए रखना चाहता है।

धारा 12. जहां आपत्ति दायर की गई है, वहां निर्धारित प्राधिकारी द्वारा अधिशेष भूमि का निर्धारण। -

(1) जहां उपधारा (2) धारा 10 के तहत या धारा 11 की उप-धारा (2) के तहत आपत्ति दायर की गई है या धारा 13 के तहत किसी अपीलीय आदेश के कारण, निर्धारित प्राधिकारी, पक्षों को सुनवाई का और साक्ष्य प्रस्तुत करने का उचित अवसर के बाद, अपने कारण दर्ज करने के बाद आपत्तियों पर निर्णय लेना और अधिशेष भूमि का निर्धारण करेगा।

(2) धारा 13 के तहत किसी भी अपीलीय आदेश के अधीन, उप-धारा (1) के तहत निर्धारित प्राधिकारी का आदेश अंतिम और निर्णायक होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

धारा 13. अपील-(1) धारा 11 या धारा 12 की उप-धारा (2) के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी पक्ष, आदेश की तारीख़ के तीस दिनों के भीतर, उस जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में है भूमि या उसका कोई भाग स्थित है।

(2) जिला न्यायाधीश यथासंभव शीघ्रता से अपील का निपटान करेगा और उस पर उसका निर्णय अंतिम और निर्णायक होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(3) जहां इस धारा के तहत अपील की जाती है, जिला न्यायाधीश उस आदेश के प्रवर्तन पर रोक लगा सकता है जिसके खिलाफ़ अपील की गई है, ऐसे समय के लिए और ऐसी शर्तों पर जो उचित और उपयुक्त मानी जा सकती हैं।

धारा 14. अधिशेष भूमि का अधिग्रहण. (1) निर्धारित प्राधिकारी -

(i) ऐसे मामले में, जहां धारा 11 की उपधारा (1) के तहत पारित आदेश अंतिम हो गया है; या

(ii) ऐसे मामले में, जहां धारा 13 के तहत कोई अपील नहीं की गई है, उसके लिए प्रदान की गई सीमा अवधि की समाप्ति के बाद; या

(iii) ऐसे मामले में, जहां निर्णय के बाद धारा 13 के तहत अपील की गई है;

जैसा भी मामला हो, धारा 11, 12 या 13 के तहत निर्धारित अधिशेष भूमि को आधिकारिक राजपत्र में सूचित करें।

(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना की तारीख़ की शुरुआत से, ऐसी सभी अधिशेष भूमि इसके बाद प्रदान किए गए को छोड़कर, राज्य को हस्तांतरित और निहित हो जाएगी, सभी बाधाओं से मुक्त हो जाएगा और ऐसी भूमि पर सभी व्यक्तियों के सभी अधिकार, स्वामित्व और हित, ऐसी तारीख़ से समाप्त हो जाएंगे।

(3) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन पर, कोई भी व्यक्ति, अधिशेष भूमि में, जिसके संबंध में अधिसूचना प्रकाशित की गई है, खातेदारसे कब्जे में किरायेदार या पट्टेदार के रूप में हित का दावा करता है , उसके तीस

दिनों के भीतर, ऐसी भूमि में अपने हित की सीमा दर्शाते हुए निर्धारित प्राधिकारी के समक्ष आपत्ति दर्ज कर सकता है।

(4) निर्धारित प्राधिकारी, लिखित रूप में दर्ज किए जाने वाले कारणों से, आपत्तिकर्ता, संबंधित खातेदार और राज्य सरकार को सुनवाई का उचित अवसर और साक्ष्य प्रस्तुत करने के बाद आपत्तियों का निपटान करेगा।

(5) उप-धारा (4) के तहत किसी आदेश से व्यथित कोई भी व्यक्ति, आदेश की तारीख़ से तीस दिनों के भीतर, उस जिला न्यायाधीश के समक्ष अपील कर सकता है जिसके अधिकार क्षेत्र में भूमि या उसका कोई हिस्सा स्थित है। जिला न्यायाधीश का आदेश अंतिम और निर्णायक होगा और किसी भी अदालत में उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।

(6) इस धारा के तहत किसी अपील की आपत्ति का निपटान करते समय, निर्धारित प्राधिकारी या जिला न्यायाधीश, जैसा भी मामला हो, पक्षों के अधिकारों के संबंध में सक्षम क्षेत्राधिकार वाले न्यायालय के किसी भी निर्णय को स्वीकार करेगा।

(7) किसी खातेदार या खातेदार के पट्टेदार के अलावा कोई भी व्यक्ति, जिसका अधिशेष भूमि में अधिकार, शीर्षक या हित को इसमें शामिल प्रावधानों के तहत मान्यता दी गई है, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, अधिशेष भूमि में कोई अधिकार, स्वामित्व या हित नहीं माना जाएगा।

(8) कलेक्टर, किसी भी समय, उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद और उप-धारा (4) और (5) के तहत पारित किसी भी आदेश के अधीन, अधिशेष भूमि पर कब्जा कर सकता है और उस उद्देश्य के लिए ऐसे बल का प्रयोग कर सकता है जो आवश्यक हो।

धारा 27. अधिशेष भूमि का बंदोबस्त.

(1) राज्य सरकार उस गांव में अधिशेष भूमि से निपटान करेगी, जिसमें सामुदायिक उद्देश्यों के लिए कोई भूमि उपलब्ध नहीं है या जिसमें गांव के गांव समाज के पास उपलब्ध भूमि 15 एकड़ से कम है, हालांकि कुल भूमि ऐसे बंदोबस्त के बाद सामुदायिक प्रयोजनों के लिए गांव में उपलब्ध भूमि 15 एकड़ से अधिक नहीं होनी चाहिए। गाँव समाज के साथ तय की गई भूमि का उपयोग पेड़ लगाने, चारा उगाने या ऐसे अन्य सामुदायिक उद्देश्यों के लिए किया जाएगा, जैसा निर्धारित किया जा सकता है।

(2) उप-धारा (1) के प्रावधानों के अधीन, जहां इस अधिनियम के तहत राज्य में निहित होने की तारीख़ से ठीक पहले कोई अधिशेष भूमि किसी सहकारी समिति के सदस्य द्वारा रखी गई थी, ऐसी भूमि, यदि समाज चाहता है, राज्य सरकार द्वारा समाज के साथ समझौता किया जाए।

(3) पूर्ववर्ती उप-धाराओं के प्रावधानों के तहत शेष बची किसी भी अधिशेष भूमि का निपटान राज्य सरकार द्वारा किया जा सकता है:

(ए) यदि गांव में शेष भूमि 15 एकड़ से कम है, तो ऐसे खातेदारों की एक सहकारी समिति के साथ, जिनमें से कम से कम तीन-चौथाई 3(18) एकड़ से कम भूमि के धारक हैं; और

(बी) यदि भूमिहीन कृषि मजदूरों की सहकारी समिति के पास गांव में शेष भूमि 15 एकड़ से अधिक है, तो इस खंड के तहत ऐसी समिति को आवंटित कुल भूमि, यदि सभी सदस्यों के बीच समान रूप से विभाजित की जाएगी प्रत्येक को 3(18) एकड़ से अधिक भूमि नहीं दी जाएगी।

(4) उप-धारा (3) के खंड (बी) के तहत निपटान के बाद बची हुई किसी भी अतिरिक्त भूमि का निपटान राज्य सरकार द्वारा किसी भी सहकारी समिति के

साथ किया जा सकता है, जिसके किसी भी सदस्य के पास ऐसे निपटान से पहले 3(18) एकड़ से अधिक भूमि स्वयं का अधिकार में नहीं है।"

5. 1972 के एक संशोधन अधिनियम द्वारा, यू.पी. 1973 का अधिनियम 18, जो 8.6.1973 को लागू हुआ, मूल अधिनियम की विभिन्न धाराओं का थोक प्रतिस्थापन किया गया। इसका सीधा सा कारण यह है कि अधिशेष "उचित गुणवत्ता भूमि" निर्धारित करने की पूर्ववर्ती योजना को अब एक ऐसी योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया जो अतिरिक्त सिंचित भूमि का निर्धारण करती थी। यहां तक कि ऐसी भूमि की अधिकतम सीमा को भी 7.3 हेक्टेयर सिंचित भूमि में बदल दिया गया था, साथ ही परिवार के आकार के आधार पर अधिकतम 6 हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि भी। एक नया धारा 13ए को अधिनियम के तहत अपीलीय प्राधिकारी को समीक्षा की शक्ति प्रदान करते हुए शामिल किया गया था। 1972 के संशोधन अधिनियम की धारा 19 में निहित अस्थायी प्रावधान में संशोधन अधिनियम के प्रारंभ के समय लंबित कार्यवाही को समाप्त करने का प्रावधान किया गया था साथ ही उन कार्यवाहियों को बचाना जो मूल अधिनियम के तहत पहले ही अंतिम हो चुकी थीं।

6. यू.पी. भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के सुसंगत प्रावधान यहां दिये गए हैं: -

"धारा 3. 1961 के यू.पी. अधिनियम I की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए नई धाराओं का प्रतिस्थापन। यू.पी.भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण अधिनियम, 1960, की धारा 3, 4, 5, 6, 7 और 8 के लिए जिसे इसके बाद मूल अधिनियम के रूप में जाना जाएगा, निम्नलिखित धाराएं प्रतिस्थापित की जाएंगी, अर्थात्: -

“...

4. अधिकतम सीमा और छूट के प्रयोजनों के लिए क्षेत्र का निर्धारण। धारा 5 के अंतर्गत अधिकतम सीमा क्षेत्र या धारा 6 के अंतर्गत किसी छूट के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए-

(i) खंड (ii) के प्रावधानों के अधीन, डेढ़ हेक्टेयर असिंचित भूमि या ढाई हेक्टेयर उपवन भूमि या ढाई हेक्टेयर ऊसर भूमि को एक हेक्टेयर सिंचित भूमि के रूप में गिना जाएगा;

(ii) निम्नलिखित क्षेत्रों में किसी में भी असिंचित भूमि का ढाई हेक्टेयर, अर्थात्-

(ए) बुन्देलखण्ड;

(बी) इलाहाबाद, इटावा, मथुरा और आगरा जिलों के ट्रांस-जमुना हिस्से;

(सी) इलाहाबाद, फ़तेहपुर, कानपुर, इटावा, मथुरा और आगरा जिलों के 16 किलोमीटर तक जमुना की गहरी धारा से सीआईएस-जमुना हिस्से

(डी) कैमूर के दक्षिण रेंज में मिर्ज़ापुर जिले का भाग;

(ई) मिर्ज़ापुर जिले में तहसील सदर के टप्पा उपरौध और टप्पा चौरासी (बलई पहाड़);

(एफ) मिर्ज़ापुर जिले में तहसील रॉबर्ट्सगंज का हिस्सा, जो कैमूर रेंज के उत्तर में स्थित है;

(जी) परगना सक्तेशगढ़ और उत्तर प्रदेश जमींदारी उन्मूलन और भूमि सुधार अधिनियम, 1950 की अनुसूची VI की सूची 'ए' और 'बी' में उल्लेखित गांव, परगना अहरौरा और मिर्ज़ापुर जिले के चुनार तहसील के भगत की पहाड़ी पट्टियों में; और

(एच) वाराणसी जिले के पूर्व तालुका नौगढ़ या चकिया तहसील में शामिल क्षेत्र;

(i) कुमाऊं और गढ़वाल मंडल के पहाड़ी और भाबर क्षेत्र और देहरादून जिले के जौनसार बावर परगना;

एक हेक्टेयर सिंचित भूमि के रूप में गिना जाएगा।

5. सीमा अधिरोपण.

(1) उत्तर प्रदेश भूमि धारण पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के प्रारंभ से, कोई भी खातेदार पूरे उत्तर प्रदेश में, कुल मिलाकर, सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने का हकदार नहीं होगा ,उस पर लागू है.

XX

(3) उपधारा (4), (5) और के प्रावधानों के अधीन और (6), उपधारा (1) के प्रयोजनों के लिए अधिकतम सीमा होगी-

(ए) पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार के खातेदारके मामले में, 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि (उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि सहित), साथ ही दो अतिरिक्त हेक्टेयर सिंचित भूमि या ऐसी अतिरिक्त भूमि जो उसके द्वारा धारित भूमि को मिलाकर, उसके प्रत्येक वयस्क पुत्र के लिए, जो या तो स्वयं खातेदार नहीं हैं या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम या सिंचित भूमि है, कुल मिलाकर दो हेक्टेयर हो जाती है, जो ऐसी अतिरिक्त भूमि के अधिकतम छह हेक्टेयर के अधीन है;

(बी) पांच से अधिक सदस्यों वाले परिवार के खातेदार के मामले में, 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि (उसके परिवार के अन्य सदस्यों द्वारा धारित भूमि सहित), इसके अलावा, पांच से अधिक सदस्यों में से प्रत्येक और उसके प्रत्येक वयस्क के लिए ऐसे पुत्र जो स्वयं खातेदारी धारक नहीं हैं या जिनके पास दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि है, दो अतिरिक्त हेक्टेयर सिंचित भूमि या ऐसी

अतिरिक्त भूमि जो ऐसे वयस्क पुत्र द्वारा धारित भूमि के साथ मिलकर दो हेक्टेयर हो जाती है, अधिकतम सीमा के अधीन ऐसी छह हेक्टेयर अतिरिक्त भूमि की ।

स्पष्टीकरण - खंड (ए) और (बी) में अभिव्यक्ति 'वयस्क पुत्र' में एक वयस्क पुत्र शामिल है जो मर चुका है और अपने पीछे जीवित नाबालिग बेटे या नाबालिग बेटियां (विवाहित बेटियों के अलावा) छोड़ गया है जो स्वयं किरायेदार नहीं हैं या जो दो हेक्टेयर से कम सिंचित भूमि रखने वाले;

(सी) कृषि में शिक्षा प्रदान करने वाले डिग्री कॉलेज के स्वामित्व धारक के मामले में, 20 हेक्टेयर सिंचित भूमि;

(डी) कृषि में शिक्षा प्रदान करने वाले एक इंटरमीडिएट कॉलेज के कार्यकाल धारक के मामले में, 12 हेक्टेयर सिंचित भूमि;

(ई) किसी अन्य खातेदार के मामले में, 7.30 हेक्टेयर सिंचित भूमि।

स्पष्टीकरण-भूमि का कोई भी हस्तांतरण या विभाजन जो उप-धारा (6) और (7) के तहत नजरअंदाज किया जा सकता है, उसे भी नजरअंदाज किया जाएगा-

(पी) यह निर्धारित करने के प्रयोजनों के लिए कि क्या खातेदार का वयस्क पुत्र खंड (ए) के अर्थ के भीतर स्वयं खातेदार है;

(क्यू) धारा 9 के तहत नोटिस की सेवा के प्रयोजनों के लिए।"

धारा 4. धारा 9 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 9 को उसकी उप-धारा (1) के रूप में पुनः क्रमांकित किया जाएगा, और उप-धारा (1) को इस प्रकार पुनः क्रमांकित करने के बाद, निम्नलिखित उप-धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात् -

"(2) उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 के लागू होने के बाद जितनी जल्दी हो सके, निर्धारित प्राधिकारी, सामान्य नोटिस की तरह, उक्त अधिनियम के प्रवर्तन पर लागू अधिकतम सीमा के अतिरिक्त भूमि रखने वाले प्रत्येक खातेदारको बुलाएगा ऐसे नोटिस के प्रकाशन के 30 दिनों के भीतर, उसे उप-धारा (1) में निर्दिष्ट एक बयान प्रस्तुत करना होगा।

(3) जहां खातेदारकी पत्नी के पास कोई भूमि है, जो अधिकतम सीमा क्षेत्रों के निर्धारण के प्रयोजनों के लिए खातेदारद्वारा रखी गई भूमि से व्यथित होने की भागी है, तो खातेदारी धारक, उपधारा (1) में निर्दिष्ट अपने बयान के साथ उस भूखंड या भूखंडों के संबंध में पसंद के लिए अपनी पत्नी की सहमति भी दाखिल करेगा जिसे वे उन पर लागू अधिकतम सीमा क्षेत्र के हिस्से के रूप में बनाए रखना चाहते हैं और जहां उनकी पत्नी की सहमति प्राप्त नहीं हुई है, वहां निर्धारित प्राधिकारी धारा 10 की उपधारा (2) के तहत नोटिस उसे अलग से तामील कराया जाएगा।"

धारा 7. नई धारा 13-ए का समावेश।

मूल अधिनियम की धारा 13 के बाद, निम्नलिखित धारा जोड़ी जाएगी, अर्थात्:

-

13-ए. कतिपय मामलों में अधिशेष भूमि का पुनः निर्धारण।

(1) निर्धारित प्राधिकारी, किसी भी समय, धारा 14 की उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना की तारीख़ से दो साल की अवधि के भीतर, रिकॉर्ड पर स्पष्ट किसी भी गलती को सुधार सकता है:

बशर्ते कि ऐसा कोई सुधार नहीं किया जाएगा जिसका प्रभाव अधिशेष भूमि में वृद्धि हो, जब तक कि निर्धारित प्राधिकारी ने ऐसा करने के अपने इरादे के बारे

में खातेदारको नोटिस नहीं दिया हो और उसे सुनवाई का उचित अवसर नहीं दिया हो।

(2) धारा 10, 11, 12, 12-ए, 13, 14 और 15 के प्रावधान उप-धारा (1) के तहत किसी भी कार्यवाही के संबंध में यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होंगे, और धारा 10 के आवेदन के प्रयोजनों के लिए, नोटिस उप-धारा (1) के परंतुक के तहत, धारा 9 के तहत एक नोटिस माना जाएगा।"

धारा 19. अस्थायी प्रावधान.

(1) मूल अधिनियम की धारा 9, धारा 10, धारा 11, धारा 12, धारा 13 या धारा 30 के तहत अधिशेष भूमि के निर्धारण के लिए सभी कार्यवाही, इस अधिनियम के प्रारंभ के समय किसी भी अदालत या प्राधिकरण के समक्ष लंबित, समाप्त हो जायेंगी और निर्धारित प्राधिकारी इस अधिनियम द्वारा सम्मिलित उस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) के तहत एक नोटिस ज़ारी करके उस अधिनियम के तहत अधिकतम क्षेत्र के निर्धारण के लिए कार्यवाही नए सिरे से शुरू करेगा:

बशर्ते कि ऐसे मामलों में अधिकतम सीमा क्षेत्र निम्नलिखित तरीके से निर्धारित किया जाएगा: -

(ए) सबसे पहले, अधिकतम सीमा का निर्धारण मूल अधिनियम के अनुसार किया जाएगा, जैसा कि इस अधिनियम द्वारा संशोधन से पहले था;

(बी) इसके बाद, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार सीमा क्षेत्र को फिर से निर्धारित किया जाएगा।

(2) उपधारा (1) में किसी भी बात के बावजूद, धारा 14 के तहत या मूल अधिनियम के अध्याय III या अध्याय IV के तहत किसी भी खातेदार के संबंध में कोई भी कार्यवाही, जिसके संबंध में अधिशेष भूमि अंतिम रूप से पहले

निर्धारित की गई है इस अधिनियम की शुरुआत, उस अधिनियम की धारा 9 की उप-धारा (2) और धारा 13-ए के प्रावधानों की प्रयोज्यता पर प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना, मूल अधिनियम के प्रावधानों के अनुसार ज़ारी और समाप्त की जा सकती है इस अधिनियम द्वारा, ऐसी भूमि के संबंध में।"

7. 17.1.1975 को यू.पी. भूमि धारण सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974, यू.पी 1975 का अधिनियम संख्या 2, लागू हुआ... दिलचस्प बात यह है कि 1972 के संशोधन में निहित नई विधायी योजना में कुछ बदलाव किए गए थे। यह अधिनियम, धारा 1 और 9 को छोड़कर, 8.6.1973 से लागू किया गया था, जो कि, जैसा कि हम पहले ही देख चुके हैं, 1972 के संशोधन अधिनियम के लागू होने की तारीख़ थी। 1974 के इस संशोधन अधिनियम ने नई स्थानापन्न योजना में केवल "एकल फसल भूमि" की अवधारणा को जोड़ा। इस अधिनियम के प्रासंगिक प्रावधान यहां नीचे दिए गए हैं: -

"धारा 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।

(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 कहा जा सकता है।

(2) यह धारा और धारा 9 एक साथ लागू होंगी, और शेष धाराएं 8 जून, 1973 को लागू मानी जाएंगी।

धारा 4. धारा 4 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 4 में, खंड (ii) में

(ए) शब्दों "किसी भी असिंचित भूमि के ढाई हेक्टेयर" के स्थान पर, "डेढ़ हेक्टेयर एकल फसल भूमि या किसी अन्य असिंचित भूमि के ढाई हेक्टेयर" शब्द रखे जाएंगे।

(बी) अंत में निम्नलिखित स्पष्टीकरण डाला जाएगा, अर्थात्: -

"स्पष्टीकरण- खंड (ii) के प्रयोजनों के लिए, अभिव्यक्ति 'एकल फसल भूमि' का अर्थ है कोई भी असिंचित भूमि जो किसी राज्य सिंचाई कार्य या निजी सिंचाई कार्य से सुनिश्चित सिंचाई के परिणामस्वरूप कृषि वर्ष में केवल एक फसल पैदा करने में सक्षम हो ।"

धारा 9. अस्थायी प्रावधान.

जहां इस अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले, किसी खातेदारके संबंध में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का आदेश मूल अधिनियम के तहत किया गया है, निर्धारित प्राधिकारी, इस अधिनियम के प्रारंभ होने से दो साल की अवधि के भीतर किसी भी समय, कर सकता है इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अधिशेष भूमि का पुनः निर्धारण करें।"

8. एक अध्यादेश, जिसने मूल अधिनियम में और संशोधन किया, 10 अक्टूबर, 1975 को लागू हुआ। उक्त अध्यादेश के समाप्त होने के बाद, 1976 का तीसरा संशोधन अधिनियम लागू किया गया, जो यू.पी. 1976 का अधिनियम 20 था, लेकिन अध्यादेश की तारीख, अर्थात् 10.10.1975 से प्रभावी था। इस संशोधन में, कई अन्य परिवर्तन किए गए जिनसे हमारा सीधा संबंध नहीं है, सिवाय इसके कि इस अपील का भाग्य इस अधिनियम की अस्थायी प्रावधान के सही संरचना पर निर्भर करता है, अर्थात् धारा 31। इस संशोधन अधिनियम की प्रासंगिक धाराएँ यहाँ दी गई हैं: -

"धारा 1. संक्षिप्त शीर्षक और प्रारंभ।

(1) इस अधिनियम को उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 कहा जा सकता है।

(2) इसे 10 अक्टूबर 1975 को लागू माना जाएगा।

धारा 8. धारा 9 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 9 में,-

(ए) उप-धारा (2) में, निम्नलिखित परंतुक जोड़ा जाएगा अर्थात्: -

"बशर्ते कि 10 अक्टूबर, 1975 के बाद किसी भी समय, निर्धारित प्राधिकारी नोटिस द्वारा, उक्त तिथि पर उस पर लागू सीमा क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले किसी भी किरायेदार को, तीस दिनों के भीतर उसे जमा करने के लिए कह सकता है। ऐसे नोटिस की सेवा की तारीख, उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विवरण या उससे संबंधित कोई भी जानकारी।";

(बी) उप-धारा (2) के बाद निम्नलिखित उप-धारा डाली जाएगी, अर्थात्: -

"(2-ए) 24 जनवरी 1971 को या उसके बाद किसी भी समय सीलिंग क्षेत्र से अधिक भूमि रखने वाले प्रत्येक खातेदारजिसने उप-धारा (2) में निर्दिष्ट विवरण प्रस्तुत नहीं किया है और जिसके संबंध में इस अधिनियम के तहत कार्यवाही 10 अक्टूबर 1975 को लंबित नहीं है, उक्त तिथि से तीस दिनों के भीतर निर्धारित प्राधिकारी को सभी भूमि के विवरण युक्त एक विवरण प्रस्तुत करना होगा-

(ए) 24 जनवरी 1971 को उनके और उनके परिवार के सदस्यों द्वारा धारित;

(बी) 24 जनवरी 1971 और 10 अक्टूबर 1975 के बीच उनके या उनके परिवार के सदस्यों द्वारा अर्जित या निपटान किया गया।"

धारा 11. धारा 14 का संशोधन.

मूल अधिनियम की धारा 14 में-

(ए) उप-धारा (2) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"(2) उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना की तारीख़ की शुरुआत से, ऐसी सभी अधिशेष भूमि राज्य सरकार को हस्तांतरित और निहित हो जाएगी ऐसी तारीख़ से, सभी बाधाओं और सभी व्यक्तियों के सभी अधिकारों से मुक्त होकर, शीर्षक और हित समाप्त हो जाएगा:

बशर्ते कि कोई बाधा हो तो उसे कुर्क किया जाएगा अधिशेष भूमि के लिए प्रतिस्थापन में धारा 17 के तहत देय राशि के लिए";

(बी) उप-धारा (3), (4), (5), (6) और (7) को हटा दिया जाएगा;

(सी) उप-धारा (8) के लिए, निम्नलिखित उप-धारा प्रतिस्थापित की जाएगी, अर्थात्: -

"(8) कलेक्टर उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना के प्रकाशन के बाद किसी भी समय अधिशेष भूमि और किसी भी असिंचित फसल या पेड़ों के फलों पर कब्जा कर सकता है, जो कि उप-धारा (1) धारा 15 की फसल या फल नहीं हैं, खातेदारया ऐसी भूमि पर कब्जे में पाए गए किसी अन्य व्यक्ति को बेदखल करने के बाद लागू होता है, और उस उद्देश्य के लिए, ऐसे बल का उपयोग कर सकता है या उपयोग करवाया जा सकता है जो आवश्यक हो सकता है:

बशर्ते कि कोई काश्तकार, किसी भी समय स्वेच्छा से कलेक्टर को उसके द्वारा धारित पूरी भूमि या उसके किसी हिस्से पर कब्जा दे सकता है, जिसे इस अधिनियम के प्रावधानों के तहत अधिशेष घोषित किया गया है या घोषित किए जाने की संभावना है, और उसके बाद उप-धारा (2) के प्रावधान ऐसी भूमि पर

वैसे ही लागू होंगे जैसे वे उप-धारा (1) के तहत अधिसूचना में निर्दिष्ट किसी अधिशेष भूमि पर लागू होते हैं।"

धारा 31. अस्थाई प्रावधान.

(1) मूल अधिनियम की धारा 14 की उप-धारा (3) से (7) के तहत सभी कार्यवाही, जैसा कि यह ठीक पहले थी उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अध्यादेश, 1976 के प्रारंभ होने की तारीख़ से ठीक पहले किसी न्यायालय या प्राधिकारी के समक्ष लंबित मामले को ऐसी तारीख़ पर समाप्त माना जाएगा।

(2) जहां किसी खातेदारके संबंध में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का आदेश 17 जनवरी 1975 से पहले मूल अधिनियम के तहत किया गया है और निर्धारित प्राधिकारी को उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974, की धारा 9 के तहत अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता है तो फिर उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 19 की उपधारा (2) में किसी बात के होते हुए भी, मूल अधिनियम धारा 13 के अंतर्गत प्रत्येक अपील या ऐसी अपील के संबंध में अन्य कार्यवाही, उक्त आदेश के विरुद्ध की गई, और अक्टूबर, 1975 के दसवें दिन से ठीक पहले लंबित, उक्त तिथि पर समाप्त मानी जाएगी।

(3) जहां किसी खातेदारके संबंध में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का आदेश अक्टूबर, 1975 के दसवें दिन से पहले मूल अधिनियम के तहत किया गया है, निर्धारित प्राधिकारी (जैसा कि मूल अधिनियम में परिभाषित है) किसी भी समय उक्त तिथि से दो वर्ष की अवधि में, इस अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करें, चाहे ऐसे आदेश

के खिलाफ़ कोई अपील दायर की गई हो या नहीं और अधिशेष भूमि निर्धारण के मूल आदेश के खिलाफ़ किसी भी अपील के बावजूद (चाहे लंबित या निर्णय लिया गया हो) ।

(4) मूल अधिनियम की धारा 13 के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ इस धारा की उपधारा (3) या उत्तर प्रदेश भूमि धारण पर अधिकतम सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा 9 के तहत अधिशेष भूमि के पुनर्निर्धारण के हर आदेश पर लागू होंगे:

बशर्ते कि तीस दिन की अवधि, उत्तर प्रदेश सीलिंग या भूमि धारण (संशोधन) अधिनियम 1974 की धारा 9 में निर्दिष्ट आदेश के खिलाफ़ अपील के मामले में गणना ऐसे आदेश की तारीख़ या 10 अक्टूबर 1975, जो भी बाद में हो, से की जाएगी।

(5) मूल अधिनियम की धारा 13-ए के प्रावधान यथोचित परिवर्तनों के साथ उत्तर प्रदेश भूमि धारण सीमा अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 की धारा के तहत या धारा 9 के तहत अधिशेष भूमि के प्रत्येक पुनर्निर्धारण पर लागू होंगे।

(6) जहां कोई मूल्यांकन रोल उप-धारा के तहत अंतिम हो गया है अन्तर्गत उप धारा (4) धारा 21 फरवरी, 1976 के सोलहवें दिन से पहले, इसे फिर से नहीं खोला जाएगा, इस अधिनियम द्वारा इसकी अनुसूची के साथ पढ़े गए मूल अधिनियम के अध्याय III में किए गए किसी भी संशोधन के बावजूद।"

9. उत्तर प्रदेश की विधायिका द्वारा बनाए गए वैधानिक कानून के इस पेंच को देखते हुए, हमने दोनों पक्षों के विद्वान वकील को सुना है। श्री सी.यू.सिंह अपीलकर्ताओं की ओर से उपस्थित विद्वान वरिष्ठ अधिवक्ता ने हमारे समक्ष कई प्रस्तुतियाँ की हैं, लेकिन अंततः प्रस्तुत किया कि धारा 31 के सही निर्माण पर, पूरी कार्यवाही समाप्त हो

गई थी, और इसलिए अपीलीय प्राधिकारी को दिनांक 13.12. 1987 को ऐसा करने का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं था। उन्होंने तर्क दिया कि धारा 31(2) और 31(3) को संयुक्त रूप से पढ़ने से पता चलेगा कि चूंकि इन उप-धाराओं की सभी अपेक्षित शर्तें पूरी हो चुकी हैं, इसलिए मूल अधिनियम की धारा 13 के तहत अपील को प्राथमिकता दी गई, जो 10वीं तारीख़ अक्टूबर, 1975 से पहले लंबित थी , उक्त तिथि पर समाप्त माना जाएगा। चूँकि 1976 के संशोधन अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अधिशेष भूमि का कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया था, विद्वान वकील के अनुसार, दो वर्ष की अवधि बहुत पहले बीत चुकी है और कोई पुनर्निर्धारण नहीं किया गया है, अधिशेष भूमि ऐसा कहा जाता है कि निर्धारित प्राधिकारी द्वारा निर्धारित किया गया है, अब इसकी कोई कानूनी शुचिता नहीं है। उन्होंने एक कमजोर तर्क दिया कि 1972 के संशोधन की धारा 19 के तहत, कार्यवाही किसी भी मामले में समाप्त हो गई थी, लेकिन हम उस तर्क को स्वीकार करने के इच्छुक नहीं थे क्योंकि संशोधन अधिनियम की धारा 9 के तहत एक सामान्य नोटिस खातेदारको दिया गया था। जिस नोटिस का जवाब उक्त खातेदारद्वारा नहीं दिया गया। ऐसा होने पर, 1972 अधिनियम की धारा 19 स्पष्ट रूप से लागू नहीं हो सकती।

10. विद्वान वरिष्ठ वकील ने हमारे सामने इस न्यायालय के दो निर्णयों का भी हवाला दिया - उत्तर प्रदेश राज्य बनाम मिथिलेश कुमारी और अन्य, 1987 (तितम्बा) एससीसी 21, और मंसूर अली खान और अन्य बनाम उत्तर प्रदेश राज्य एवं अन्य, (1992) 1 एससीसी 737 । हालाँकि, इनके बाद से किसी निर्णय का वर्तमान मामले के तथ्यों पर कोई सीधा अनुप्रयोग नहीं है, हम उनसे निपटना आवश्यक नहीं समझते हैं।

11. दूसरी ओर, श्री गर्ग ने यू.पी. राज्य की ओर से जोरदार तर्क दिया कि धारा 31 (2) के तहत शर्तों को पूरा नहीं किया गया है, उक्त धारा लागू नहीं है, और ऐसा होने पर, अपीलीय प्राधिकारी ने सही ढंग से आगे बढ़कर मामले को गुण-दोष के आधार

पर सुना और अपील खारिज़ कर दी। उनका मुख्य तर्क यह है कि 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 31(2) की प्रयोज्यता से पहले दो शर्तें हैं। सबसे पहले, अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला एक आदेश होना चाहिए जो 17.1.1975 से पहले के मूल अधिनियम के तहत बनाया गया है; और दूसरा, निर्धारित प्राधिकारी को 1974 संशोधन अधिनियम की धारा 9 के तहत अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने की आवश्यकता होनी चाहिए। उनके निवेदन में वर्तमान मामले के तथ्यों पर दूसरी पूर्व-आवश्यकता पूरी नहीं की गई है। उन्होंने तर्क दिया, ऐसा इसलिए है क्योंकि 1974 के संशोधन अधिनियम की धारा 9 ने निर्धारित प्राधिकारी को विवेक दिया है जो 1972 के संशोधन द्वारा किए गए संशोधन के अनुसार "अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित कर सकता है"। विद्वान वकील के अनुसार, वर्तमान तथ्यों पर अधिशेष भूमि के पुन: निर्धारण का अवसर उत्पन्न नहीं हुआ, क्योंकि तथ्यों पर बहुत कम या कोई असिंचित भूमि नहीं है जिसे 1972 अधिनियम के धारा 4 में निहित सूत्र के अनुसार सिंचित भूमि में परिवर्तित करने की आवश्यकता है, और इसलिए 1972 संशोधन अधिनियम के अनुसार किया गया निर्धारण, जो वास्तव में दिनांक 13.1.1975 के आदेश द्वारा किया गया था, इस निष्कर्ष पर पहुंचेगा कि वह आदेश कायम रहेगा और उस पर दोबारा विचार करने की आवश्यकता नहीं है।

12. इसलिए, राज्य के लिए विद्वान वकील का तर्क, हमें विचाराधीन चार अधिनियमों का थोड़ा बारीकी से विश्लेषण करने के लिए प्रेरित करता है। शुरुआत में एक बात स्पष्ट हो जाती है: 1960 की मूल वैधानिक योजना, जिसमें अधिशेष "उचित गुणवत्ता वाली भूमि" की बात की गई थी, को 1974 के संशोधन अधिनियम के साथ पढ़े गए 1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा एक पूरी तरह से नई और अलग योजना द्वारा प्रतिस्थापित किया गया था। जैसा कि ऊपर देखा गया है, ये दोनों अधिनियम, कुछ मामूली अपवादों के साथ, एक ही तारीख, अर्थात् 8.6.1973 को लागू हुए। नई वैधानिक योजना होगी इसमें आवश्यक रूप से "उचित गुणवत्ता वाली भूमि" के स्थान

पर "सिंचित भूमि" शामिल है। दोनों मामलों में सीमा क्षेत्र भी पूरी तरह से अलग है। इस मामले में, अब 1974 के संशोधन की धारा 9 का अर्थ समझना इस पृष्ठभूमि में महत्वपूर्ण है। ज्ञात हो कि धारा 9 स्वयं ही लागू होती है केवल 17.1.1975 को। धारा 9 को लागू करने के लिए, किसी खातेदार के संबंध में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का एक आदेश बनाना होगा संशोधन अधिनियम की शुरूआत से पहले । धारा 1(2) द्वारा, "यह धारा" और धारा 9 दोनों एक साथ यानी 17.1.1975 को लागू हुईं। अभिव्यक्ति "यह धारा" धारा 1(1) को संदर्भित करती है जो बदले में अधिनियम को यू.पी.भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 के रूप में संदर्भित करती है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि अधिनियम केवल 17.1.1975 को शुरू हुआ है, हालांकि कई धाराएं पूर्वव्यापी रूप से यानी 8.6.1973 को लागू मानी जाएंगी। निर्धारित प्राधिकारी द्वारा पारित आदेश 13.1.1975 को होने के कारण धारा 9 की पहली शर्त पूरी होती है, अर्थात यह आदेश 17.1.1975 से पहले पारित किया गया है। यह अनुभाग का दूसरा भाग है जिस पर बहुत सारी बहस हुई है। राज्य के विद्वान वकील के अनुसार "हो सकता है" अभिव्यक्ति के प्रयोग से विवेक निर्धारित प्राधिकारी में निहित हो जाता है। हम यह जोड़ने में जल्दबाजी कर सकते हैं कि यह अभिव्यक्ति "दो साल की अवधि के भीतर किसी भी समय हो सकती है..." यू.पी. भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1976 की धारा 31(3) में भी आती है। यह उपधारा यह स्पष्ट करती है कि अभिव्यक्ति "हो सकता है" शब्दों के साथ "दो वर्ष की अवधि के भीतर किसी भी समय..." के साथ जाती है क्योंकि यह स्पष्ट है कि उप-धारा के सही पढ़ने पर, निर्धारित प्राधिकारी को, हर मामले में, अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करना होगा यदि अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला आदेश अक्टूबर, 1975 के 10 वें दिन से पहले किया गया हो। विचार यह है कि एक अवधि यू.पी. भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1974 द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने के लिए दो साल का

समय दिया गया है। इस मामले में, यह स्पष्ट है कि अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने के लिए निर्धारित प्राधिकारी में कोई विवेक निहित नहीं है। सभी मामलों में, अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित किया जाना है, क्योंकि सभी भूमि पर लागू होने वाली एक पूरी तरह से अलग और नई योजना ने मौजूदा योजना का स्थान ले लिया है। एकमात्र अपवाद वह है, जहां 8.6.1973 से पहले, अधिशेष भूमि का निर्धारण अंतिम रूप से किया गया है, यानी, धारा 13 के तहत एक अपील का निपटारा किया गया है।

13. मामले को थोड़ा अलग नजरिये से देखा जा सकता है. 1972 के संशोधन अधिनियम की धारा 19, जो एक अस्थायी प्रावधान है, उक्त अधिनियम के प्रारंभ होने पर लंबित कार्यवाही के निवारण का प्रावधान करती है। हमने पहले ही संकेत दिया है कि 1972 के संशोधन अधिनियम द्वारा सम्मिलित धारा 9(2) के तहत एक सामान्य नोटिस के मुद्दे पर 1967 की लंबित कार्यवाही को नए सिरे से शुरू करना था, जो वास्तव में किया गया था। इस प्रकार, 13.1.1975 का आदेश अधिनियम की धारा 19(1) का परिणाम है। तथ्यों पर धारा 19(2) इस साधारण कारण से लागू नहीं होती है कि इस मामले में अधिशेष भूमि का निर्धारण 1972 अधिनियम के प्रारंभ होने से पहले अंतिम रूप से नहीं किया गया था, अर्थात, इस तारीख़ पहले मूल अधिनियम की धारा 13 के तहत अपील पर निर्णय नहीं लिया गया था।

14. यह हमें यू.पी. भूमि धारण पर अधिकतम सीमा लगाना (संशोधन) अधिनियम, 1976 में निहित अस्थायी प्रावधान पर लाता है। धारा 31(2) के तहत, स्पष्ट रूप से, वर्तमान मामले में अधिशेष भूमि का निर्धारण करने का आदेश 17.1.1975 से चार दिन पहले किया गया था और इस प्रकार पहली शर्त या पूर्व-आवश्यकता अनुभाग के आवेदन के लिए पूरा हो गया है। दूसरी पूर्व-आवश्यकता भी इस साधारण कारण से पूरी की गई है कि 1974 अधिनियम की धारा 9, जो 1972 संशोधन अधिनियम के समान विधायी योजना का हिस्सा है, इस कारण से लागू होगी कि अधिशेष भूमि का निर्धारण करने वाला आदेश उक्त अधिनियम का प्रारंभ, अर्थात्,

17.1.1975 से पहले बनाया गया था (जो 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 31(2) के आवेदन के लिए पहली पूर्व-आवश्यकता के समान है)। ऐसा होने पर, धारा 31(2) की भाषा यह स्पष्ट करती है कि ऐसे आदेशों के खिलाफ़ की गई प्रत्येक अपील और 10 अक्टूबर, 1975 से ठीक पहले लंबित, उक्त तिथि को समाप्त मानी जाएगी। तथ्यों के आधार पर, हमें सूचित किया गया है कि इस तिथि से पहले एक अपील दायर की गई थी।

15. यह मामला होने पर, निर्धारित प्राधिकारी के लिए 1976 अधिनियम द्वारा संशोधित मूल अधिनियम के अनुसार धारा 31(3) के तहत अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करना आवश्यक था, जिसके लिए धारा 13 के प्रावधान लागू किए गए थे ,मूल अधिनियम इस धारा की उपधारा 3 या 1974 संशोधन अधिनियम की धारा 9 (1976 संशोधन अधिनियम की धारा 31(4) के तहत) के तहत अधिशेष भूमि को फिर से निर्धारित करने वाले प्रत्येक आदेश पर यथोचित परिवर्तनों के साथ लागू होगा। वर्तमान मामले में तथ्यों के आधार पर ऐसा कभी नहीं किया गया है, यह स्पष्ट है कि 1975 में दायर अपील समाप्त हो गई है और इसलिए अतिरिक्त आयुक्त, आगरा द्वारा गुण- दोष के आधार पर सुनवाई नहीं की जा सकती है। ऐसा होने पर, आयुक्त द्वारा दिनांक 13.1.1975 को पारित निर्णय और आदेश क्षेत्राधिकार के बिना है।

16. अब केवल अपीलीय प्राधिकारी और उच्च न्यायालय के तर्क पर विचार करना बाकी है। अपीलीय प्राधिकारी और उच्च न्यायालय दोनों का विचार था कि यू.पी. भूमि धारण पर सीमा का अधिरोपण (संशोधन) अधिनियम, 1972 की धारा 9(2) के तहत कोई नया नोटिस ज़ारी नहीं किया गया था। तथ्यों के आधार पर हमें बताया गया है कि वास्तव में ऐसा नोटिस 24.11.1975 को ज़ारी किया गया था। इसके बावजूद, अपीलीय प्राधिकारी और उच्च न्यायालय ने कटौती के खिलाफ़ निर्णय लेने की अपनी चिंता में, गलत ठहराया है कि ऐसा कोई नोटिस ज़ारी नहीं किया गया था। जो भी हो, यह स्पष्ट है कि धारा 31 के तहत छूट संशोधित धारा 9(2) के तहत किसी नोटिस के

ज़ारी होने या न ज़ारी होने पर निर्भर नहीं करती है। यह मामला होने के कारण, नोटिस ज़ारी न करने के तथ्य का पता लगाना यह स्वयं एक गैर-मुद्दा है, इसलिए इसे आगे बढ़ाना हमारे लिए अनावश्यक है। केवल यह दोहराना आवश्यक है कि 1976 के संशोधन अधिनियम के तहत कोई भी नई कवायद निर्धारित प्राधिकारी द्वारा नहीं की गई थी, जैसा कि 1976 के संशोधन अधिनियम की धारा 31(3) के लिए आवश्यक है। यह मामला होने पर, उच्च न्यायालय के विवादित फैसले को अनिवार्य रूप से रद्द किया जाना चाहिए। इसलिए लागत के संबंध में बिना किसी आदेश के अपील स्वीकार की जाती है।

अपील की अनुमति।

यह अनुवाद आर्टिफ़िश्यल इंटेलिजेंस टूल "सुवास" की सहायता से अनुवादक अधिवक्ता चित्रा भदौरिया द्वारा किया गया है।

अस्वीकरण- इस निर्णय का अनुवाद स्थानीय भाषा में किया जा रहा है, एवं इसका प्रयोग केवल पक्षकार इसको समझने के लिए उनकी भाषा में कर सकेंगे एवं यह किसी अन्य प्रयोजन में काम नहीं ली जायेगी। सभी आधिकारिक एवं व्यवहारिक उद्देश्यों के लिए उक्त निर्णय का अंग्रेजी संस्करण ही विश्वसनीय माना जायेगा एवं निष्पादन एवं क्रियान्वयन में भी उसी को उपयोग में लिया जायेगा।